जनजातीय समुदायों को सशक्त बनाना

भारत में जनजातीय कल्याण के लिए सरकारी पहल

भारत जनजातीय समुदायों का एक जीवंत और विविध श्रेणी का घर है, 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 10.45 करोड़ या कुल आबादी का 8.6% दर्ज की गई है। ये समुदाय, जिनमें 705 से अधिक अलग-अलग समूह शामिल हैं, देश भर में फैले हुए हैं, जो अक्सर दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इन आदिवासी समुदायों की सहायता और समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान देने के साथ उनके उत्थान के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं और नीतियां शुरू की हैं।

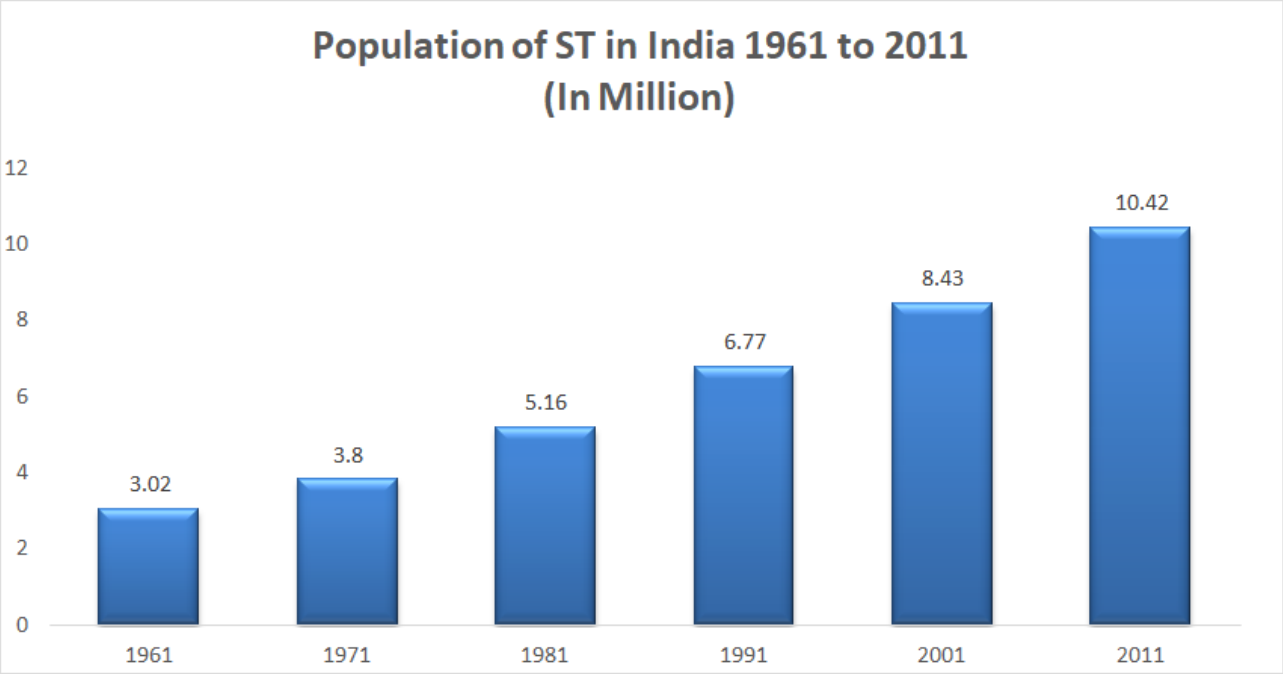

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और सरकारी प्रतिबद्धता

जनजातीय विकास की दिशा में भारत सरकार के समर्पित प्रयास 1974-75 में जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के कार्यान्वयन के समय से चले आ रहे हैं, जो अनुसूचित जनजाति घटक (एसटीसी) और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) के रूप में विकसित हुई। इन योजनाओं ने सुनिश्चित किया कि विभिन्न मंत्रालय जनजातीय कल्याण के लिए समन्वित दृष्टिकोण के साथ काम करें। वित्तीय प्रतिबद्धता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, डीएपीएसटी बजट सालाना ₹25,000 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹1.2 लाख करोड़ हो गया है। केंद्रीय बजट 2024-25 ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए आवंटन को बढ़ाकर ₹13,000 करोड़ कर दिया है, जो पिछले वर्ष के अनुमान से 73.60% की वृद्धि दर्शाता है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ

2 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के हजारीबाग में **"धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान"** लॉन्च किया। ₹79,150 करोड़ से अधिक की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य लगभग 63,000 आदिवासी गांवों में सामाजिक बुनियादी ढांचे,, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अंतर को पाटना है। इस अभियान का लाभ 549 जिलों और 2,740 ब्लॉकों में फैले 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 करोड़ से अधिक आदिवासी लोगों को मिलेगा। यह अभियान भारत सरकार के 17 मंत्रालयों और विभागों द्वारा 25 हस्तक्षेपों को एकीकृत करता है।

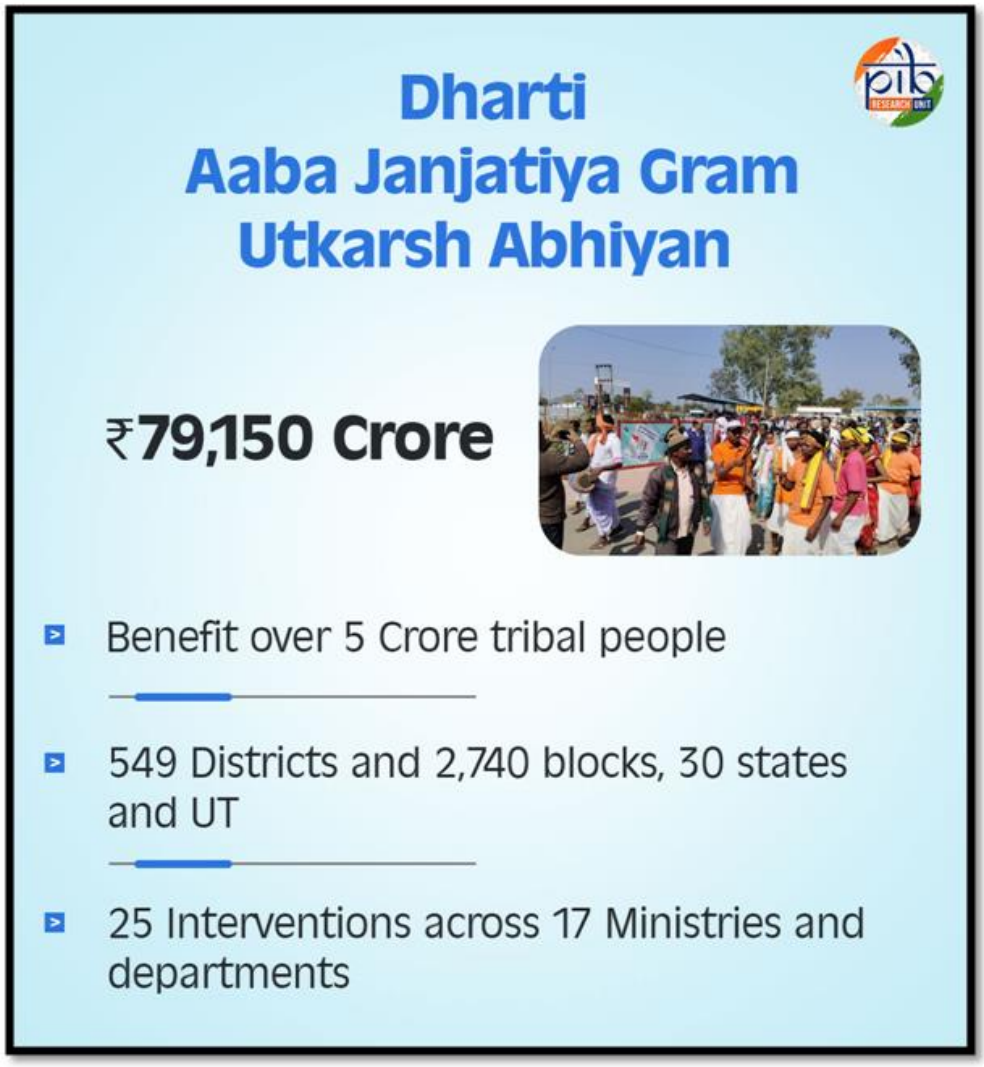

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

आदिवासी समुदायों के लिए सरकार की शिक्षा पहल का एक प्रमुख घटक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) है। इन स्कूलों का लक्ष्य दूरदराज के इलाकों में आदिवासी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच आसान हो सके। शैक्षणिक और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करके, ईएमआरएस आदिवासी सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। प्रत्येक स्कूल में कक्षा VI से XII तक 480 छात्र रहते हैं।

जनजातीय समुदायों के लिए शैक्षिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए, प्रधानमंत्री ने 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) का उद्घाटन किया और 2,800 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले 25 ईएमआरएस की आधारशिला रखी। इन स्कूलों को नवोदय विद्यालयों के बराबर डिजाइन किया गया है और ये खेल और कौशल विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय आदिवासी कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करते हैं।

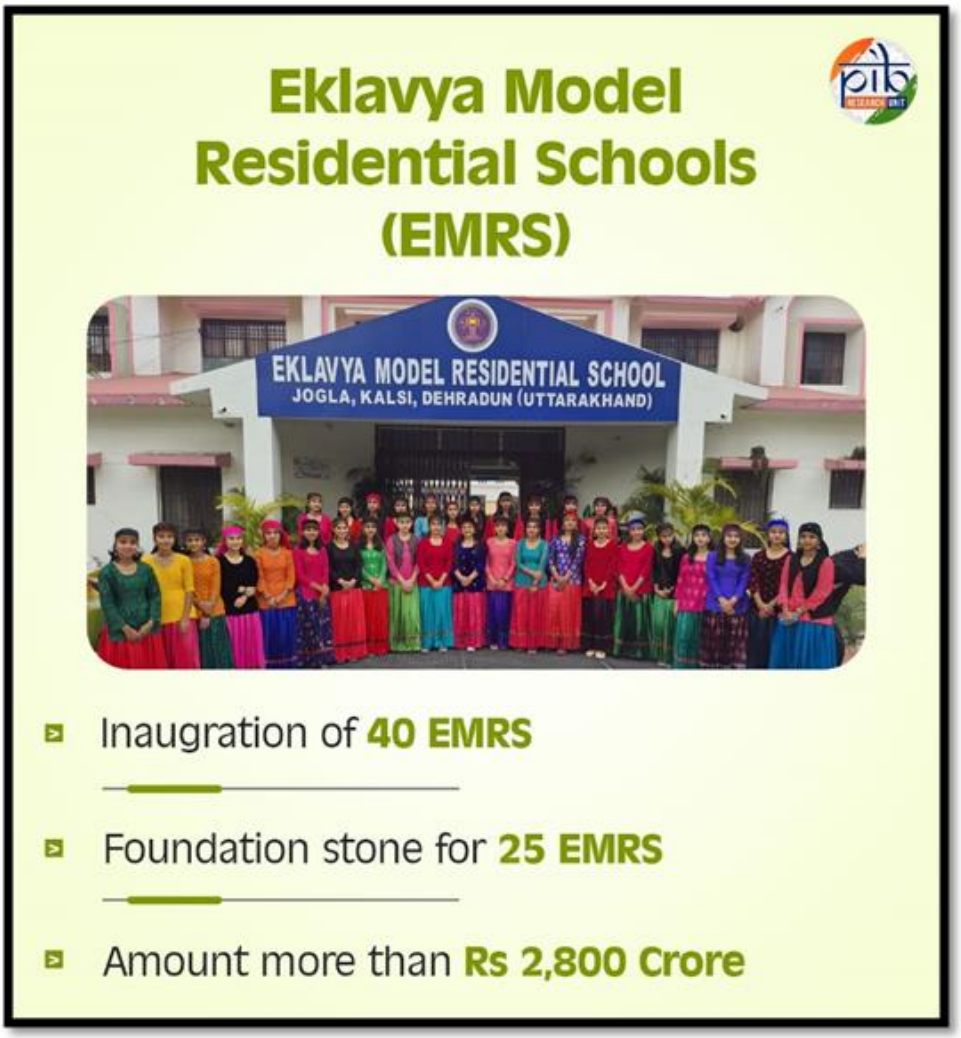

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

धरती आबा कार्यक्रम के साथ-साथ, प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के तहत परियोजनाओं की नींव भी रखी। ₹1,360 करोड़ से अधिक की ये परियोजनाएं सड़क कनेक्टिविटी में सुधार, आंगनबाड़ियों और बहुउद्देशीय केंद्रों के निर्माण और स्कूल छात्रावासों के निर्माण पर केंद्रित हैं। सरकार ने 75,800 से अधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) घरों के विद्युतीकरण की भी घोषणा की और 275 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों और 500 आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन किया। इसके अतिरिक्त, 250 वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं, और 5,550 से अधिक पीवीटीजी गांवों को "नल से जल" योजना के तहत स्वच्छ पेयजल तक पहुंच प्रदान की गई है।

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ

1. प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ

इन छात्रवृत्तियों का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और आदिवासी छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देना है:

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति: कक्षा नौवीं और दसवीं में एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति: ग्यारहवीं कक्षा से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले एसटी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

2. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना

यह योजना मेधावी एसटी छात्रों को विदेश के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट अध्ययन करने के अवसर प्रदान करती है। यह योजना उत्कृष्टता और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पर केंद्रित है, और सरकार हर साल 20 पुरस्कार प्रदान करती है, जिसमें 30% महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं

3. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) विकास कार्यक्रम

पीवीटीजी कार्यक्रम स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, स्वच्छ पानी और बिजली तक पहुंच में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए सबसे कमजोर आदिवासी समुदायों को लक्षित करता है। इस पहल के तहत 200 जिलों की 22,000 बस्तियों में लगभग 7 लाख पीवीटीजी परिवार व्यापक विकास योजनाओं से लाभान्वित होते हैं।

4. जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता

टीआरआई आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने और उनकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। टीआरआई को सहायता योजना जनजातीय कल्याण, भाषाओं, परंपराओं और औषधीय प्रथाओं पर अनुसंधान और दस्तावेज़ीकरण को बढ़ावा देती है, साथ ही सांस्कृतिक उत्सवों और विनिमय कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है।

5. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी)

डीएपीएसटी योजना यह सुनिश्चित करती है कि सभी केंद्रीय मंत्रालय जनजातीय कल्याण के लिए योजनाएं लागू करें, जिसमें 41 मंत्रालय समन्वय में काम कर रहे हैं। यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने पर केंद्रित है, जिसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन किया गया है।

6. एसटी छात्रों के लिए राष्ट्रीय फैलोशिप

यह फ़ेलोशिप योजना पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले आदिवासी छात्रों को सहायता करती है, जिससे डिजीलॉकर एकीकरण के माध्यम से समय पर वित्तीय सहायता और शिकायत निवारण सुनिश्चित होता है।

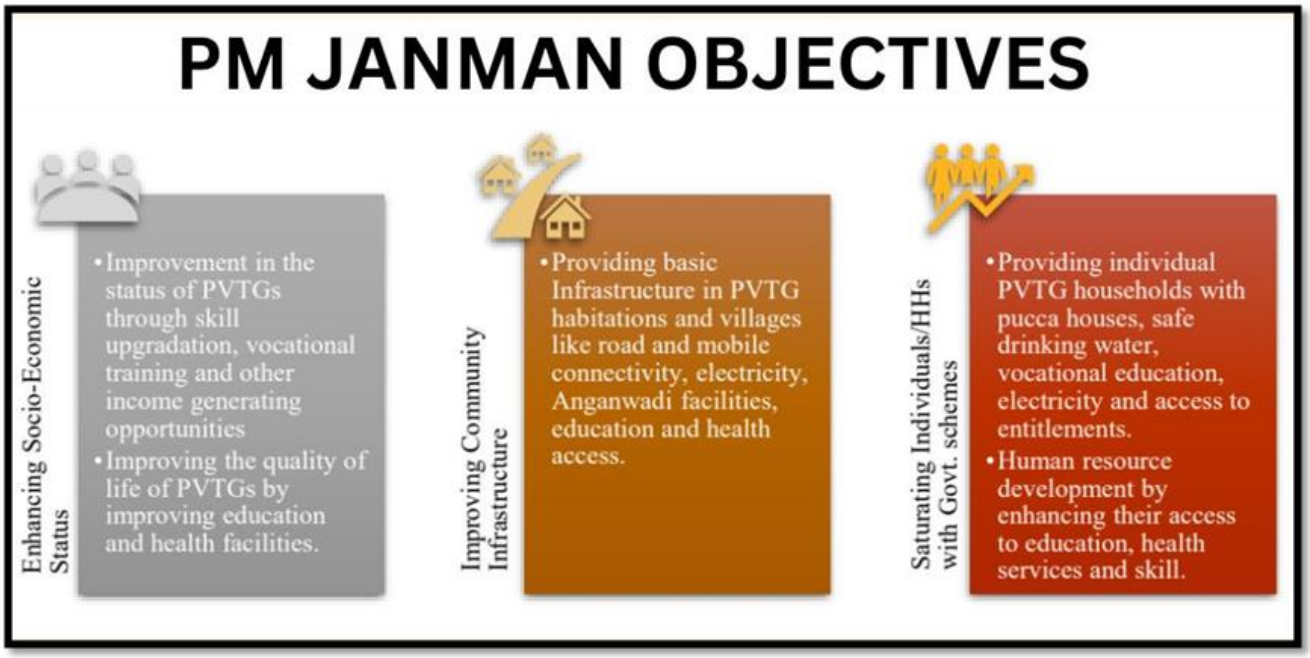

7. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी)

एनएसटीएफडीसी आय-सृजन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, रियायती ब्याज दरों पर एसटी लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

8. भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड)

ट्राइफेड अपने ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देता है, जिससे जनजातीय कारीगरों को स्थायी आजीविका के अवसर मिलते हैं। हस्तशिल्प, कपड़ा और अन्य जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देकर, ट्राइफेड इन समुदायों के लिए बाजार से संबंध बनाता है।

9. आदि महोत्सव एवं सांस्कृतिक उत्सव

ये त्योहार आदिवासी विरासत को प्रदर्शित करने के मंच हैं, जिसमें आदि महोत्सव एक उल्लेखनीय कार्यक्रम है। वे प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का हिस्सा हैं, जो आदिवासी कौशल विकास, विरासत संवर्धन और आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस 2022 पर अपने संबोधन के दौरान जिन अन्य प्रभावशाली योजनाओं पर प्रकाश डाला गया उनमें स्वच्छ भारत मिशन, जैविक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोबरधन योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना शामिल हैं, जो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य का समर्थन करती है। ये पहल आदिवासी समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

सरकार ने आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, विशेष रूप से आय सृजन और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। सावधि ऋण योजना व्यावसायिक इकाइयों के लिए ऋण प्रदान करती है, जो 5 से 10 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि के साथ इकाई लागत का 90% तक आसान ऋण प्रदान करती है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) आदिवासी महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो केवल 4% ब्याज पर ₹2 लाख तक का रियायती ऋण प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, माइक्रो क्रेडिट योजना प्रति एसएचजी को ₹5 लाख तक के ऋण की पेशकश करके आदिवासी स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का समर्थन करती है। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) आदिवासी छात्रों को आसान ऋण प्रदान करती है, जिससे उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान ब्याज सब्सिडी के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलती है। इन योजनाओं का उद्देश्य उद्यमिता, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहित करके आदिवासी आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।

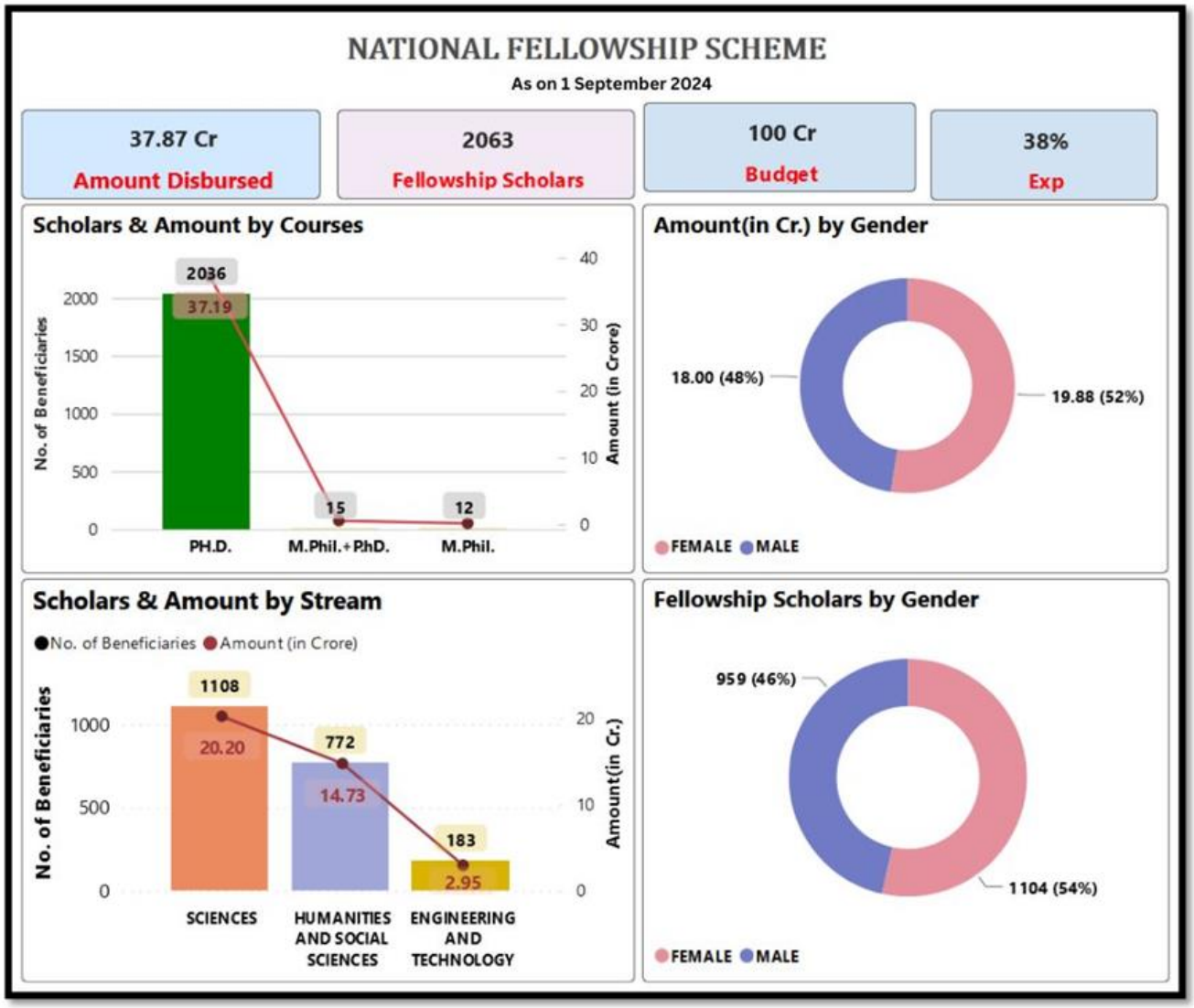

पिछले वर्षों में जनजातीय कार्य मंत्रालय का बजट

बेहतर बुनियादी ढाँचा और आजीविका के अवसर

प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (PMAAGY) का उद्देश्य महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। योजना के तहत, 50% आदिवासी आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति (एसटी) वाले 36428 गांवों की पहचान इन गांवों में बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई है, जिसमें नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों के गांव भी शामिल हैं।

बेहतर स्वास्थ्य परिणामों के लिए पहल

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सिकल सेल रोग (एससीडी) सहित हीमोग्लोबिनोपैथी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्यों को एक व्यापक दिशानिर्देश विकसित और वितरित किया है। मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में आदिवासी आबादी के बीच प्रचलित आनुवंशिक रक्त विकार एससीडी के गंभीर प्रभाव को पहचानते हुए, सरकार ने इसके लगभग पूर्ण उन्मूलन की दिशा में प्रयास तेज कर दिए हैं। इस उद्देश्य से, प्रधान मंत्री द्वारा 1 जुलाई, 2023 को मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया गया था।

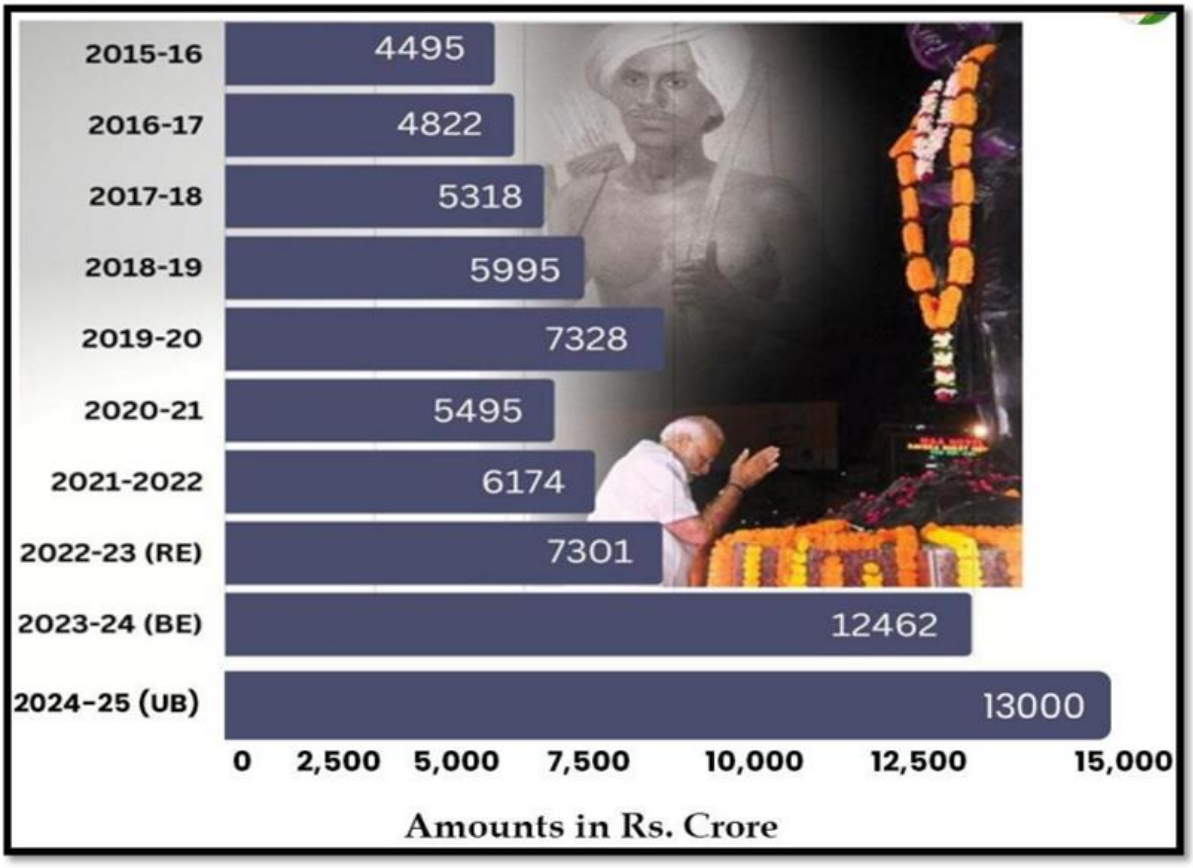

यह मिशन सभी एससीडी रोगियों को सस्ती और सुलभ देखभाल प्रदान करने, उपचार की गुणवत्ता में सुधार करने और जागरूकता अभियान, सार्वभौमिक स्क्रीनिंग और परामर्श सेवाओं के माध्यम से बीमारी की

व्यापकता को कम करने पर केंद्रित है। यह केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच सहयोग पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सबसे कमजोर आदिवासी आबादी को इन प्रयासों से लाभ मिले।

एससीडी पहल के अलावा, मिशन इंद्रधनुष जैसी अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का लक्ष्य आदिवासी समुदायों पर विशेष ध्यान देने के साथ दो साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। इस मिशन का विस्तार मुफ्त कोविड-19 टीके उपलब्ध कराने के लिए भी किया गया है, जिससे आदिवासी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एक अन्य उल्लेखनीय कार्यक्रम निक्षय मित्र पहल है, जो तपेदिक (टीबी) रोगियों को अतिरिक्त नैदानिक, पोषण और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है, जिनमें से कई आदिवासी समुदायों से हैं। इस पहल का उद्देश्य कमजोर आबादी के समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करके टीबी से प्रभावी ढंग से निपटना है।

इसके अलावा, जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता (टीआरआई) योजना, टीआरआई को अनुसंधान, दस्तावेज़ीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए सशक्त बनाने का प्रयास करती है। ये संस्थान ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करके जनजातीय विकास में योगदान देते हैं।

भारत के जनजातीय समुदायों का सम्मान और जश्न मनाना

उन राज्यों में 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय स्वीकृत किए गए हैं जहां आदिवासी रहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करते थे और झुकने से इनकार करते थे। 01 नवंबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम को विकसित करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने का आह्वान किया। मानगढ़ धाम, राजस्थान-गुजरात सीमा के पास स्थित, वह स्थान है जहां 1913 में अंग्रेजों द्वारा सामूहिक गोलीबारी में 1500 से अधिक भील स्वतंत्रता सेनानियों की जान चली गई थी। मानगढ़ धाम को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों की संयुक्त परियोजना के रूप में विकसित किया जाएगा, जो आदिवासी विरासत और उनकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाले एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों के साथ-साथ इन सभी पहलों ने आदिवासी समुदायों को उनकी संस्कृतियों, विरासतों और जीवन के तरीकों का सम्मान करते हुए मुख्यधारा में लाने का मार्ग प्रशस्त किया है।

निष्कर्ष

जनजातीय सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की पहल ने इन समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से, भारत सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आदिवासी समुदायों को विकास के अंतर को पाटने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए आवश्यक सहायता मिले। पीएम धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष

अभियान और ईएमआरएस और पीएम-जनमन जैसी अन्य पहल आदिवासी आबादी को सशक्त बनाने और भारत की विकास कहानी में उनका समावेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

संदर्भ

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2060243

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2055996

Annual Report 2023-24: https://tribal.nic.in/KnowledgeHub.aspx

ST in India revealed in Cenus 2011 report: https://tribal.nic.in/downloads/statistics/3-STinindiaascensus2011.pdf

https://adiprasaran.tribal.gov.in/pm-janman01/man.aspx

Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan (Manthan Shivir) September 2024: https://adiprasaran.tribal.gov.in/pm-janman/photoAlbumjjgd1.aspx

https://tribal.nic.in/EMRS.aspx

https://tribal.nic.in/KnowledgeHub.aspx

PM-JANMAN-Operational Guidelines: https://adiprasaran.tribal.gov.in/pm-janman/photoAlbumjjgd1.aspx

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2036245

https://pib.gov.in/FeaturesDeatils.aspx?NoteId=151692&reg=3&lang=1

https://dashboard.tribal.gov.in/

***

एमजी/आरपीएम/केसी/ जीके

(Release ID: 2061352)